आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 42 लखनऊ, शनिवार 14 फरवरी 2026 सा 20 फरवरी 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

पीएमओ का नया पता हुआ सेवा तीर्थ, नागरिक देवो भव मंत्र के साथ प्रधान सेवक मोदी ने दिया बड़ा राजनीतिक संदेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'सेवा तीर्थ' परिसर का उद्घाटन करते हुए एक बार फिर अपनी उस राजनीतिक और प्रशासनिक सोच को रेखांकित किया, जिसमें सत्ता को सेवा का माध्यम बताने पर जोर रहा है। यह वही विचार है जिसे मोदी वर्षों से "प्रधान सेवक" की अपनी पहचान के साथ जोड़ते रहे हैं। नए परिसर में अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक साथ काम करेंगे। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में स्थित था। उद्घाटन के दौरान मोदी ने 'सेवा तीर्थ' की पट्टिका का अनावरण किया, जिस पर देवनागरी में इसका नाम अंकित है और नीचे 'नागरिक देवो भव' का आदर्श वाक्य लिखा है। यह संदेश सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को नागरिक केंद्रित बनाने की सोच को दर्शाता है। इस मौके पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इससे समन्वय बेहतर होगा और निर्णय प्रक्रिया तेज

बनेगी।यदि पिछले एक दशक के कदमों को देखा जाए तो यह केवल भवन परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रतीकों की राजनीति और प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का प्रयास भी है। २०१४ के बाद से केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक विरासत से जुड़े नामों और प्रतीकों को बदलने की दिशा में कई फैसले लिए। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री आवास वाले मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग किया गया। देखा जाये तो 'सेवा तीर्थ' उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, जहां सत्ता के पारंपरिक शक्ति केंद्रों को सेवा और कर्तव्य की भाषा में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। स्पष्ट है कि मोदी सरकार शासन की भाषा और प्रतीकों को बदलकर एक ऐसा संदेश देना चाहती है, जिसमें सरकार खुद को शासक नहीं, सेवक के रूप में प्रस्तुत करे और 'सेवा तीर्थ' उसी विचार का ताजा उदाहरण बनकर उभरा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में पहला फैसला महिलाओं और किसानों के संदर्भ में लिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और फिर अपने एक संबोधन के जरिये सबका मार्ग प्रशस्त किया।

एपस्टीन मामले को लेकर हरदीप सिंह पुरी पर कांग्रेस का तीखा हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने जेफरी एपस्टीन के साथ कथित संबंधों पर सवाल उठाते हुए पुरी को पद पर बने रहने के अयोग्य बताया। एएनआई से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि स्पष्ट रूप से, कांग्रेस पार्टी हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले ४८ घंटों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। हम इस मुद्दे को देश की जनता के सामने उठाएंगे कि यह सरकार भ्रष्ट है, और वह भी जेफरी एपस्टीन जैसे व्यक्ति के साथ। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पुरी के हालिया साक्षात्कारों की आलोचना की। खेड़ा ने कहा कि वे कहते हैं, 'अगर कुछ हुआ होता, तो मैं आपको बता देता।' जरा सोचिए, उनकी मानसिकता देखिए। 'अगर कुछ हुआ होता, तो मैं आपको बता देता।' मैं इससे स्तब्ध रह गया। तथाकथित एपस्टीन फाइल्स से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए खेड़ा ने दावा किया कि इस मामले के चलते सात देशों के नेताओं ने

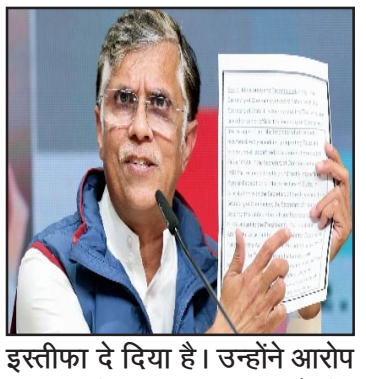

इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी भी इसमें शामिल हैं। पुरी के बयानों को गुमराह करने वाला बताते हुए खेड़ा ने कहा कि पुरी ने दावा किया कि जब वे पहली बार एपस्टीन से मिलने गए थे, तो उन्हें जगह का पता नहीं था क्योंकि एक ड्राइवर उन्हें वहां ले जा रहा था। एपस्टीन से मिलने जाते समय मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने गूगल पर अपनी मंजिल खोजी और फिर खुद से पूछा कि क्या मुझे एपस्टीन से मिलना चाहिए। उन्होंने पुरी के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, जब यह सब हुआ तब हरदीप सिंह पुरी बच्चे थे? पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए खेड़ा ने कहा कि यह दावा कि हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से सिर्फ एक बार मिले थे, गलत है। दरअसल, हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से कई बार मिले थे। उन्होंने एपस्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पुरी की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। एपस्टीन द्वारा २००८ में अदालत में दोषी ठहराए जाने के बावजूद, पुरी ने कहा था कि हममें से कुछ लोगों को एपस्टीन के आपराधिक रिक र्ड पर संदेह था। खेड़ा ने जवाब दिया, ष्एपस्टीन के कबूलनामे के बाद भी, हमारे मंत्री हरदीप पुरी को २०१४ में संदेह था। वह एक मंत्री हैं, और यह उनके नैतिक मूल्यों का स्तर है। ऐसी स्थिति में, हरदीप पुरी को कैसे उचित ठहराया जा सकता है?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी का पलटवारः गालिब की शायरी के जरिए सपा की विफलताओं पर साधा निशाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके व्यवहार से बेटियां घबरा

गईं और व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आलोचना को प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब के एक कथन से समाप्त किया, 'धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा,' जिसका अर्थ है कि विपक्ष अपनी गहरी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राज्य को शर्मिंदा किया, और दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में लगभग ६ करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि राज्य की छवि अचानक खराब नहीं हुई। यह समाजवादी पार्टी का विशेष व्यवहार था जिसने बेटियों को घबरा दिया और व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। विपक्ष के भाषण का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। और गालिब ने कहा था, 'उमर भर मैं यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा।' इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि नीति आयोग के आंकड़ों पर आधारित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने पिछले ८ वर्षों में ६ करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी की रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अन्य योजनाओं से वंचित किया जाए। उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाएं मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण के साथ शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में ६ करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बजट सत्र ६ फरवरी से २० फरवरी तक चलेगा, और २०२६–२७ वित्तीय वर्ष का राज्य बजट ११ फरवरी को पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि २०२५ के महाकुंभ में ६५ करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे, और प्रयागराज में आयोजित २०२६ के माघ मेले में २१ करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। सत्र से पहले, समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल को सरकार के दावों को दोहराने के बजाय अपना भाषण देना चाहिए और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पार्टी इसका विरोध करेगी।

सम्पादकीय

पूर्व सैन्यकर्मियों की किताबों पर पहराः क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पारदर्शिता से समझौता हो रहा है?

पूर्व सेनाध्यक्ष एम.एम. नरावणे की किताब 'फोर स्टार्स अ फ डेस्टिनी' को लेकर उठे विवाद के बाद अब खबर है कि केंद्र पूर्व सैन्यकर्मियों की किताब के प्रकाशन के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बारे में रक्षा मंत्रालय में हाल में बैठक हुई, जिसमें ऐसे मामलों में सरकारी गोपनीयता कानून के प्रावधानों को भी लागू करने पर विचार हुआ। अभी जो कायदा है, उसमें इस अधिनियम के प्रावधान शामिल नहीं हैं। दरअसल, कार्यरत सैन्यकर्मियों के मामलों में तो विभिन्न वैधानिक एवं सेवा संबंधी शर्तें लागू होती हैं, लेकिन रिटायर्ड कर्मियों की किताबों का प्रकाशन को रोकने का कानून तो दूर, सेवा संबंधी नियम भी तय नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर ये समझ बनी है कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के प्रकाशनों से राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी ना हो, और ना ही गोपनीय समझी जाने वाली सूचनाएं सार्वजनिक हो पाएं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि रिटायर्ड सैन्य कर्मी भले सेना कानून या सेना के नियमों से बंधे हुए ना हों, मगर गोपनीयता संबंधी नियम उन पर भी लागू होते हैं। मगर मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उसके संदर्भ में गोपनीय सूचनाओं की परिभाषा क्या है तथा उसे कौन तय करेगा? क्या इस मामले में सरकार राष्ट्रीय बहस कराएगी, जिसमें विपक्षी विचारों को भी व्यक्त होने का पूरा अवसर मिले? क्या नए कायदे राजनीतिक आम सहमति से तय होंगे या सत्ता पक्ष खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र प्राधिकारी मानते हुए नियम तय कर देगा? यह समझ समस्याग्रस्त है कि सेना में अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह नहीं करते अथवा सत्तासीन लोग विपक्षी दलों या नेताओं की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिक बड़े पहरुआ हैं। विपरीत नजरिया यह है कि अधिकतम संभव पारदर्शिता किसी सिस्टम के अंदर मौजूद कमियों दूर करने में अधिक सहायक होती है। किसी किताब से ऐसा प्रकरण या आम चलन सार्वजनिक होता है, जिससे नुकसान हुआ हो, तो उसे सामने आने दिया जाना चाहिए। असल में उस पर पर्देदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा कहीं अधिक क्षतिग्रस्त होगी।

कयामत तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी में एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अपने कड़े रुख को दोहराया और कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी नहीं किया जाएगा, यहां तक घ्कि कयामत तक भी नहीं। श्री राम जानकी मंदिर में १०वें श्री हनुमान विराट महायज्ञ और श्री रामार्चा पूजन के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कथनी और करनी में विश्वास रखती है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार जो कहती है वही करती है और जो करती है वही कहती है। हमने कहा था, श्राम लल्ला, हम आएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे,श और हमने ठीक वैसा ही किया। बाबरी ढांचे पर अपने रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम आज फिर कह रहे हैं, कयामत के दिन तक। और चूंकि वह दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की उम्मीद रखने वाले भ्रम में जी रहे

हैं। मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जिन्हें उन्होंने अवसरवादी बताया और कहा कि कुछ लोग भगवान राम को केवल संकट के समय ही याद करते हैं और बाकी समय उन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भगवान राम पहले ही भूल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार, अतीत में राम भक्तों पर गोली चलाने वाले या धार्मिक कार्यों में बाधा डालने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून का सम्मान करने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकों को श्कयामत के दिनश का इंतजार करने के बजाय भारत के कानूनी ढांचे के अनुसार जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए। योगी ने कहा कि इस देश के कानून का पालन करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। कानून तोड़ने का रास्ता सीधे सजा की ओर ले जाता है। कानून तोड़कर जन्नत का सपना देखने वाला कोई भी व्यक्ति भ्रम में जी रहा है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं से भी जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की २५ नवंबर को अयोध्या यात्रा का जिक्र किया, जब राम मंदिर पर भव्य भगवा झंडा फहराया गया था। उन्होंने कहा कि भगवा झंडा भारत के गौरव और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक बना रहेगा और उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सराहाः आधुनिक तकनीक और सेवा भाव से हृदय रोगों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा केजीएमयू

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में आयोजित दो दिवसीय 'कॉर्डिक न २०२६' के पहले दिन शुक्रवार को शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केजीएमयू आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। यहां न केवल प्रदेश और देश, बल्कि पड़ोसी देशों से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दिन–रात सेवा कर मरीजों की जिंदगी बचा रहे हैं। वे कॉर्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मेलन को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केजीएमयू का लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग प्रतिदिन गंभीर हृदय रोगियों का सफल उपचार कर उन्हें नया जीवन दे रहा है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के कारण संस्थान हृदय चिकित्सा के

क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सम्मेलन में देशभर से आए विशेषज्ञों ने नवीनतम शोध और उपचार पद्धतियों पर चर्चा की। इस आयोजन ने चिकित्सकों को अनुभव साझा करने और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद, लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. ऋषि सेट्ठी, डॉ. अक्षय प्रधान, डॉ. गौरव चौधरी, डॉ. शरद चन्द्रा, डॉ. प्रवेश विश्वकर्मा, डॉ. धीमान कहाली सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. ऋषि सेट्ठी ने कहा खराब खानपान और भागदौड़ भरी जीवनशैली के कारण डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये तीनों बीमारियां मिलकर हृदय रोग का खतरा कई गुना बढ़ा देती हैं। लापरवाही बरतने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। डॉ. ऋषि सेट्ठी ने बताया कि डायबिटीज के कारण रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है और हृदय तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मोटापा, विशेषकर पेट पर चर्बी बढ़ना, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है। हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक बढ़ा बीपी हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज के साथ बीपी या मोटापा भी है तो हृदय रोग की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। कॉर्डियोल जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. धीमान कहाली ने कहा कि दिल की बीमारी से बचाव के लिए मोटापा नियंत्रित रखना, नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार अपनाना जरूरी है। मीठा और नमक का सेवन सीमित करें तथा फास्ट फूड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। डॉ. अक्षय प्रधान ने सलाह दी कि ३० वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से ब्लड शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा टहलना, तले–भुने भोजन से परहेज, धूम्रपान से दूरी और वजन नियंत्रित रखना हृदय को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। डॉ. मोनिका, डॉ. अभिषेक, डॉ. आयुष शुक्ला और डॉ. उमेश त्रिपाठी ने भी अपना अनुभव साझा किया।

बच्चों की आस्था और श्रद्धालुओं का उत्साह, लोधेश्वर महादेवा मेले में भक्ति की अद्भुत झलक

बाराबंकी। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेवा मंदिर का फागुनी मेला अब अपने पूरे शबाब पर है। मेला क्षेत्र हर–हर बम–बम के जयकारों से गुंजायमान है। हाईवे से लेकर मंदिर तक जाने वाले मार्गों पर कांवरियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही और पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से पट गया है। श्रद्धालु कानपुर, उन्नाव, बिठूर, उरई और जालौन सहित दूर–दराज जनपदों से सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कंधों पर कांवर लेकर महादेवा पहुँच रहे हैं। डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते–झूमते कांवरियों के जत्थे पैदल मार्गों पर आगे बढ़ रहे हैं। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर–ट्र ली और बसों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की पूजा–अर्चना के बाद कई श्रद्धालु मेला परिसर में विश्राम कर भजन–कीर्तन और रामायण पाठ में जुटे हैं। भक्ति रस में डूबे कांवरियों के जत्थे उत्साह के साथ नृत्य करते भी नजर आ रहे हैं। मेले में सजी दुकानों पर खरीदारी को लेकर भीड़ बढ़ गई है। भोंपू, टोपी और पूजन सामग्री की दुकानों पर कांवरियों की विशेष भीड़ देखी जा रही है, जिससे बाजार की रौनक बढ़ गई है। इसी क्रम में लखनऊ के बन्थरा क्षेत्र से लगभग ७५ कांवरियों का जत्था महंत रामकरन की अगुवाई में जल भरकर शुक्रवार को महादेवा मंदिर पहुंचा। विधिवत पूजा–अर्चना कर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख–समृद्धि की कामना की। जत्थे में ६ से १५ वर्ष तक के बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा करते दिखाई दिए। आस्था के आगे कठिनाइयां भी फीकी पड़ती नजर आईं। अरुण कुमार, अर्जुन, दीपक, जितेंद्र, धर्मेंद्र, दिलीप, सजीवन, हिमांशु, अमित, शिवम और सुरेंद्र सहित अनेक श्रद्धालु कांवर लेकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर की ओर बढ़ते रहे। समाजसेवियों व शिव भक्तों द्वारा मेला क्षेत्र में जगह–जगह भंडारे भी चलाए जा रहे। रामनगर : लोधेश्वर महादेवा मंदिर आ रहे कांवरियों के लिए शाम ढलते ही हाईवे की दूरी तय करना बहुत ही मुश्किल भरा साबित हो रहा। हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था न होना कांवरियों को खास अखर रहा है। मार्ग के अंधेरे में डूबे रहने से वाहनों की आवाजाही के बीच दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बताते चलें कि देर रात जलाभिषेक के लिए आने–जाने वाले कांवरियों को अंधेरे में पैदल चलना पड़ रहा है। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के चलते हर समय हादसे का खतरा बना रहता है, लेकिन अब तक प्रकाश व्यवस्था की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। वहीं केसरीपुर रेलवे क्र सिंग पर भी कांवरियों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। क्र सिंग का गेट बंद कर दो–दो ट्रेनों के गुजरने तक रास्ता बंद रहने से लंबा जाम लग जाता है। इस दौरान पैदल चल रहे कांवरियों को भी काफी देर तक रुकना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा प्रभावित हो रही है।

मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, बन भी गई तो टिक नहीं पाएगी

लखनऊ। मुर्शिदाबाद में नई 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को बाबर के नाम पर मस्जिद के निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि यह मस्जिद नहीं बनेगी और अगर बन भी गई तो टिक नहीं पाएगी। एएनआई से बात करते हुए मौर्य ने जोर देकर कहा कि भारत भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के भक्तों का देश है, 'बाबर के भक्तों का नहीं'। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है, विरोध तो नाम को लेकर है। मौर्य ने कहा कि यह (मस्जिद) नहीं बनेगी और अगर बन भी गई तो टिक नहीं पाएगी। यह भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के भक्तों का देश है, बाबर के भक्तों का नहीं। हमें मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री

अनिल राजभर ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी लुटेरे के नाम पर मस्जिद का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नई मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। राजभर ने कहा कि मस्जिद बनाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश करता है, या अगर कोई भारत विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति किसी हमलावर के नाम पर ऐसा करता है, तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और पश्चिम बंगाल की जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यह देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बहुत बुरा है। इससे पहले, बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर जन उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने गुरुवार को विश्वास जताया कि मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में नई 'बाबरी मस्जिद' का निर्माण होगा, और कहा कि मुस्लिम समुदाय इसके निर्माण का समर्थन करता है।

अवैध संबंध में पड़ोस महिला और उसके बेटे ने की थी किसान की हत्या

हरदोई। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के संडीला कोतवाली क्षेत्र में किसान की सिर कूचकर की गई हत्या के आरोप में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है। आपत्तिजनक हालत में देखे जाने पर हुए विवाद के बाद यह जघन्य वारदात अंजाम दी गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने शुक्रवार को बताया कि संडीला कोतवाली क्षेत्र के मीतो गांव में ११ फरवरी की सुबह किसान व पशुपालक हुकुम सिंह (५२) का शव उसके खेत किनारे बने पशु बाड़े के छप्पर में चारपाई पर पड़ा मिला था। सिर पर भारी वस्तु से कई वार किए गए थे। हत्या के बाद शव को चारपाई पर लिटाकर ऊपर से रजाई ओढ़ा दी गई थी। मृतक के पुत्र रणजीत की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन स्थानीय पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर शक पड़ोस में रहने वाली महिला जमुना देवी और उसके पुत्र अमन पर गया। कड़ाई से पूछताछ में अमन ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि उसकी मां जमुना देवी और हुकुम सिंह के बीच प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन वह अपनी मां को खोजते हुए हुकुम सिंह के छप्पर तक पहुंचा, जहां दोनों एक ही बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में मिले। विरोध करने पर हुकुम सिंह से कहासुनी हुई और उसने अमन को थप्पड़ मार दिया। इस अपमान से तिलमिलाए अमन ने पास पड़ी ईंट से ताबड़तोड़ वार कर हुकुम सिंह की हत्या कर दी। हत्या के बाद अमन और उसकी मां ने मिलकर शव को चारपाई पर लिटाया और ऊपर से रजाई डालकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अमन की निशानदेही पर खून से सनी ईंट बरामद की है। पुलिस ने आरोपी अमन को हत्या तथा उसकी मां जमुना देवी को हत्या में सहयोग और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी के समता संवर्धन मार्च निकालने पर बवाल, छात्रों ने किया हंगामा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब विभिन्न छात्र संगठनों ने यूजीसी के समर्थन में 'समता संवर्धन मार्च' निकालने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में छात्रों के जुटने की सूचना पर पुलिस ने आरआरएफ के साथ मिलकर परिसर और मुख्य मार्गों पर घेराबंदी कर दी। छात्र गेट नंबर तीन से गेट नंबर एक तक मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया गया। विरोध में छात्र सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। मार्च राष्ट्रीय छात्र आह्वान के समर्थन में आयोजित किया गया था। छात्रों की मांग थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आध

ारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से कानूनी उल्लंघन माना जाए और प्रशासन से स्वतंत्र, स्वायत्त समान अवसर एवं भेदभाव निरोधक निकाय बनाए जाएं। साथ ही राज्य स्तर पर 'उच्च शिक्षा सामाजिक न्याय आयोगष के गठन की मांग भी उठाई गई। छात्र संगठनों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों में लगभग ११८ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो मौजूदा तंत्र की कमजोरी को दर्शाती है। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च की पूर्व सूचना देने के बावजूद भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें रोका गया और जिला प्रशासन ज्ञापन लेने तक नहीं पहुंचा। प्रदर्शन में आइसा, एनएसयूआई, एससीएस, बीएएसएफ, एसएफआई, बाप्सा, युवा और अंबेडकरवादी विद्यार्थी संघ समेत कई संगठनों के छात्र शामिल रहे। छात्र नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की कार्रवाई बताते हुए कहा कि समानता और जवाबदेही की मांग आगे भी जारी रहेगी।

पायनियर मॉडल म न्टेसरी स्कूल में 'बाल उत्सव २.०' का भव्य आयोजन, बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को मिला नया मंच

लखनऊ। पायनियर मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में "बाल उत्सव कार्यक्रम प्रगति, स्वाभिमान और सफलता की ओर २.०" का आयोजन अत्यंत उत्साह, गरिमा और प्रेरक वातावरण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री विपिन कुमार द्वारा सभी विजेता छात्र–छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। विजेता

समन्वयक बालिका शिक्षा, सुश्री सविता शुक्ला ने की, जबकि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, श्री श्याम किशोर तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर "मेरे बदलाव की कहानी" एवं "पोस्टर मेकिंग" प्रतियोगिताओं का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। जनपद के विभिन्न विद्यालयों से चयनित छात्र–छात्राओं ने इन प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते हुए अपनी रचनात्मकता, विचारशीलता और अभिव्यक्ति क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। दोनों प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पाँच पाँच छात्र–छात्राओं का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कार्यक्रम में जिला विद्यार्थियों के सुगमकर्ताओं (मार्गदर्शक शिक्षकों) को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रतिभागी छात्र–छात्राओं एवं उनके अध्यापकों के लिए कार्यक्रम स्थल पर भोजन की समुचित व्यवस्था भी की गई। जिला स्तर पर चयनित छात्र–छात्राएं अब मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए और अधिक व्यापक मंच प्राप्त होगा। यह बाल उत्सव कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्वाभिमान, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सार्थक और प्रेरणादायी पहल के रूप में सफल रहा।

पोस्टमार्टम व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी, यहां पढ़ें डिटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में शव–विच्छेदन (पोस्टमार्टम) की व्यवस्था को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष द्वारा जारी शासनादेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार, निजी मेडिकल कॉलेजों को उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम–१९५६ के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शव उपलब्ध कराए जाएंगे। इन संस्थानों में नियुक्त फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के शिक्षक और रेजिडेंट चिकित्सक शव परीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कर सकेंगे। हालांकि, जिन मामलों में जघन्य अपराध या बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम आवश्यक होगा, ऐसे प्रकरण निजी मेडिकल कॉलेजों को संदर्भित नहीं किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों जैसे केजीएमयू, आर एम एल आई एमएस, एसजी पीजीआई, यूपी यूएमएस, बीएचयू, एएमयू तथा एम्स गोरखपुर और रायबरेली में जहां फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग उपलब्ध है, वहां पोस्टमार्टम कार्य उसी विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि जहां पोस्टमार्टम हाउस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति शवों के आवंटन और प्रक्रिया की निगरानी करेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण और संचालन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, रिपोर्टिंग और अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

मणिपुर हिंसा मामलों की निगरानी करेगा उच्च न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम सुझाव

नई दिल्ली। कोर्ट ने २०२३ के मणिपुर जातीय हिंसा मामलों से संबंधित ११ एफआईआर की जांच कर रही है, दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह सुझाव भी दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के बजाय, क्षेत्राधिकार रखने वाला मणिपुर उच्च न्यायालय, जिसमें एक नए मुख्य न्यायाधीश हैं, या गुवाहाटी उच्च न्यायालय, या दोनों ही हिंसा मामलों में मुकदमों और संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी करें। इसमें केंद्र और मणिपुर सरकारों से राज्य में जातीय हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। अदालत द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मित्तल, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी

और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल हैं, ने अब तक पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों पर कई रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। मणिपुर में ३ मई, २०२३ को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से २०० से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यह हिंसा तब शुरू हुई जब पहाड़ी जिलों में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था। शुरुआत में हाल ही में दिवंगत हुई महिला पीड़ितों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उनकी जगह उनकी मां को पेश किया जाए और आरोप लगाया कि सीबीआई ने उन्हें यह भी सूचित नहीं किया कि उनके बलात्कार मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। ग्रोवर ने कहा कि कुकी समुदाय की महिला की पिछले महीने एक बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसका कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद हुए आघात से संबंध था।

रक्षा प्रमुख अनिल चौहान का बड़ा खुलासा, नेहरू ने तिब्बत पर क्यों किया था चीन से पंचशील समझौता?

नई दिल्ली। रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने शुक्रवार को स्वतंत्रता के बाद के भारत–चीन संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि १९५४ का पंचशील समझौता, जिसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को दिशा देने के लिए शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व सहित पांच सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। देहरादून में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को अपनी सीमाएँ स्वयं निर्धारित करनी पड़ीं। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के दावों से अवगत थे, जिनमें पूर्व में मैकमोहन रेखा और लद्दाख के कुछ क्षेत्र शामिल थे, लेकिन उनका मानना घ्था कि पंचशील ढांचे के माध्यम से एक व्यापक समझ संबंधों को स्थिर करने में सहायक हो सकती है। सीडीएस ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेज चले गए और यह भारत को तय करना था कि सीमा कहाँ है। नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में मैकमोहन रेखा जैसी हमारी कुछ सीमाएँ हैं और लद्दाख क्षेत्र में भी हमारा कुछ दावा है, लेकिन वह यहाँ नहीं है। इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। लगभग ८६० किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का काम करती थी। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत की तथाकथित मुक्ति के

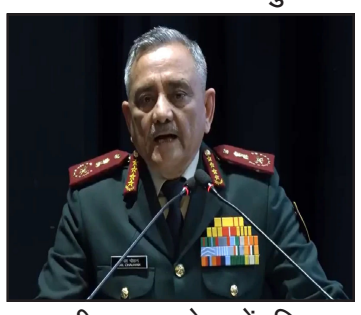

बाद चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता था। और चीन के लिए भी। जब उन्होंने तिब्बत को एक तरह से मुक्त कराया, तो वे ल्हासा में घुस गए। वे शिनजियांग में घुस गए। यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों पर बेहद अशांत था। उन्होंने कहा कि इसलिए इस क्षेत्र को कुछ प्राथमिकता दी गई। इसलिए वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे। स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था। १९५४ में, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ, भारत ने मान लिया कि उसने अपनी सीमा, उत्तरी सीमा, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम औपचारिक संधि के माध्यम से सुलझा नहीं पाए थे, सुलझा लिया है।

मीना मंच व पावर एंजिल्स कार्यशाला में निखरी नेतृत्व क्षमता, जीवन कौशल और आत्मविश्वास की सीख

लखनऊ। वार्ड संसाधन केंद्र हजरतगंज, नगर क्षेत्र जोन–एक में मीना मंच तथा पावर एंजिल्स के सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता विकास, जीवन कौशल शिक्षा और सेल्फ एस्टीम (आत्मसम्मान) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय

कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन खण्ड शिक्षा अधिकारी जोन–एक डॉ. पूनम मिश्रा तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र जोन–तीन श्री प्रमेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में नगर क्षेत्र जोन–एक एवं जोन–तीन के मीना मंच सुगमकर्ताओं को बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर श्रीमती शशि प्रभा सिंह एवं श्रीमती स्वप्निल सुमन मौर्य ने प्रतिभागियों को "प्रगति के पंख", "आधा फूल" कॉमिक बुक्स, "अरमान" मॉड्यूल, पोक्सो एक्ट तथा टूल–१० जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक गतिविधियों और सहभागितापूर्ण तरीकों से विस्तारपूर्वक समझाया। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता, नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा जीवन कौशल आधारित शिक्षा को विद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने समूह चर्चा, रोल प्ले, केस स्टडी और गतिविधि आधारित अभ्यासों के माध्यम से विषयों की गहन समझ विकसित की। समापन सत्र में खण्ड शिक्षा अधिकारी जोन–एक डॉ. पूनम मिश्रा ने कहा कि मीना मंच और पावर एंजिल्स जैसे मंच केवल औपचारिक गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि यह बालिकाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि "जब हमारी बालिकाएँ आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति सजग होंगी, तभी समाज सशक्त बनेगा। विद्यालयों में इन गतिविधियों का नियमित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है।" खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र जोन–तीन श्री प्रमेन्द्र शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन कौशल शिक्षा आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और सही–गलत की समझ भी देनी चाहिए। मीना मंच के माध्यम से हम बालिकाओं को न केवल जागरूक बना रहे हैं, बल्कि उन्हें नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर कर रहे हैं।" उन्होंने सभी सुगमकर्ताओं से अपेक्षा की कि वे कार्यशाला में प्राप्त प्रशिक्षण को अपने–अपने विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करें, जिससे बालिकाओं का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यशाला के समापन अवसर पर नगर क्षेत्र जोन–एक एवं जोन–तीन के शिक्षकगण उपस्थित रहे। आयोजन की व्यवस्थाओं में विनोद शर्मा, रूबल मिश्रा, सोनी, उत्कर्ष पाण्डेय,

इन्दु प्रकाश एवं राजू ने व्यवस्था सहायक के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। दो दिवसीय यह कार्यशाला शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी सिद्ध हुई, जिससे विद्यालयों में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल को नई गति मिली।

दरगाह शरीफ थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में दंपती कां किया गिरफ्तार

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की दरगाह शरीफ थाना पुलिस ने हत्या की एक घटना का २४ घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हंसिया और ईंट भी बरामद की है। पुलिस

के अनुसार थाना दरगाह शरीफ में धारा १०३(१)ध्२३८६१(२) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। वादिनी लक्ष्मी ने तहरीर देकर बताया था कि उनके पति बड़कू १० फरवरी को दोपहर करीब ११ बजे खेत देखने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान ११ फरवरी को उनका शव गेहूं के खेत में मिला। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान ग्राम विशुनपुर राह निवासी जसवंत उर्फ लौड़ाऊ तथा उसकी पत्नी नीलम को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि मृतक बड़कू का नीलम से पूर्व परिचय था, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। इसी रंजिश में दोनों ने मृतक को बहाने से खेत की ओर बुलाया और ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हंसिया और एक ईंट बरामद की गई। घटना के समय पहने गए कपड़े भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज ग्राम विशुनपुर राह के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

विकसित भारत का संकल्पः प्रधानमंत्री मोदी बोले- गुलामी के प्रतीक मिटाकर बना रहे स्वतंत्र भारत की पहचान

नई दिल्ली। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन १ और २ का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम सभी एक नए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। १३ फरवरी का यह दिन भारत के विकास पथ में एक नई शुरुआत का गवाह है। आज हम सभी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि साउथ ब्ल क और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें, जो ब्रिटिश सोच की हुकूमत को लागू करने के लिए बनी थीं, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। मोदी ने कहा कि यहां से जो फैसले होंगे, वे किसी महाराजा की सोच को नहीं, बल्कि १४० करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस समय २१वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। यह आवश्यक है कि विकसित भारत की कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों और इमारतों में भी दिखाई दे। जहां से देश का संचालन होता है, वह जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसे पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थीं। करीब १०० साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थीं। इसके अलावा भी अनेक चुनौतियां थीं। मैं समझता हूं कि इन चुनौतियों के बारे में बताया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे, आजादी के

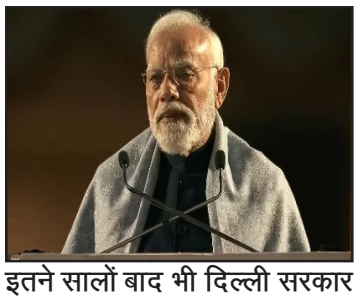

इतने सालों बाद भी दिल्ली सरकार के अनेक मंत्रालय दिल्ली के ५० से भी ज्यादा स्थानों से चल रहे हैं। प्रतिवर्ष इन स्थानों के किराये में डेढ़ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज ८ १० हजार कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में यह बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने गुलामी की मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम पर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाया। रेसकोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। यह केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, यह सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। मोदी ने कहा कि हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है, जो हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और हमारे भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ता है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थीं और न ही आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया और आज वह स्थान परिवारों, बच्चों और देशभर से आने वाले नागरिकों के लिए जीवंत स्थल बन चुका है। नाम बदलने की पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही हैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान। गुलामी से मुक्त निशान।

एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही पर डीजीसीए का एक्शन, बिना परमिट उड़ान भरने पर लगा १ करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर वैध एयरवर्थनेस परमिट के बिना आठ बार एयरबस विमान उड़ाने के लिए ११०,३५० अमेरिकी डॉलर (लगभग १ करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। एक गोपनीय आदेश के अनुसार, डीजीसीए का कहना है कि इस चूक से एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। यह

जुर्माना एयरबस ए३२० विमान से संबंधित है, जिसने २४ और २५ नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई मार्गों पर अनिवार्य एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के बिना यात्रियों को यात्रा कराई। एआरसी नियामक द्वारा विमान के सुरक्षा और अनुपालन जांच उत्तीर्ण करने के बाद प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। दिसंबर में र यटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई घटना की एयर इंडिया द्वारा की गई आंतरिक जांच में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा किया गया और एयरलाइन की अनुपालन संसेंति को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया गया। ५ फरवरी को जारी एक गोपनीय दंड आदेश में, भारतीय अधिकारियों ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को बताया कि इस घटना ने ष्जनता के विश्वास को और कमजोर किया है और संगठन के सुरक्षा अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एयर इंडिया के संयुक्त महानिदेशक मनीष कुमार ने विल्सन का जिक्र करते हुए लिखा, एयर इंडिया की ओर से उत्तरदायी प्रबंधक उपरोक्त चूक के लिए दोषी पाया गया है। एयरलाइन को ३० दिनों के भीतर १ करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह नियामक कार्रवाई एयर इंडिया की भीषण विमानन दुर्घटना के बाद कड़ी निगरानी में आई है, जिसमें पिछले साल जून में अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें २६० लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की एयरबस दुर्घटना की जांच में पायलटों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पाया गया कि आठों उड़ानों के पायलटों ने उड़ान भरने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन को हाल के महीनों में आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना विमान संचालन और अन्य ऑडिट संबंधी कमियों के लिए डीजीसीए से चेतावनी भी मिली है।

नक्सल आतंक पर 'फाइनल प्रहार', उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताई डपेपवद २०२६ की डेडलाइन

छत्तीसगढ़। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि जनवरी २०२४ से राज्य में ५३२ नक्सली मारे गए हैं, २००४ गिरफ्तार किए गए हैं और २,७०० ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ३१ मार्च तक माओवादी खतरे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह विभाग की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शर्मा ने यह भी कहा कि निरंतर सुरक्षा अभियान और पुनर्वास प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प स्पष्ट है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि ३१ मार्च, २०२६ तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्णतः उन्मूलन हो सके। शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जनवरी २०२४ से अब तक एके–४७ राइफलें, इंसास राइफलें, सेल्फ लोडिंग राइफलें, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल सहित लगभग १,१०० हथियार बरामद किए हैं। माओवादी संगठन के छह पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्य मारे गए हैं, जबकि दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान कुल १७ विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य मारे गए,

सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया। शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या गिरफ्तारियों से अधिक हो जाएगी। उन्हों ने मौजूदा रुझान को संतोषजनक बताया। राज्य में सात पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं। अब तक, इन केंद्रों में ४१० महिलाओं सहित लगभग १,७०० पूर्व नक्सलियों ने विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि २३२ वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को मोबाइल फोन सहित स्वागत किट प्रदान की जाती है ताकि वे समाज से फिर से जुड़ सकें। शर्मा ने आगे बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं और रायपुर में जागरूकता दौरे आयोजित किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर, सरायपाली और पड़ोसी राज्यों के रेडियो स्टेशनों के माध्यम से आत्मसमर्पण की अपील प्रसारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है, जिसमें स्कूल, बिजली, पेयजल, अस्पताल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं शामिल हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के हर कोने में संविधान का पालन हो।

उत्तर पुस्तिका में मिले रुपये तो छात्र पर होगी कार्रवाई, परीक्षाफल भी रुकेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में रुपये पाए जाते हैं तो बोर्ड उसे नकल सामग्री मानते हुए कार्रवाई करेगा। ऐसे छात्र का परीक्षाफल रोक दिया जाएगा, साथ ही संबंधित कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष २०२६ की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं १८ फरवरी से शुरू होकर १२ मार्च को सम्पन्न होंगी। निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने के लिए बोर्ड ने यह कदम उठाया है। बोर्ड के सचिव की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ परीक्षार्थी अनजाने में या भ्रामक धारणाओं के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के भीतर मुद्रा (धनराशि) नत्थी कर देते हैं। यह न केवल परीक्षा अनुशासन के विरुद्ध है, बल्कि परीक्षार्थी के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थियों को पूर्व में ही स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री या मुद्रा रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। कक्ष निरीक्षकों को भी इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा सम्पन्न होने के बाद क पियों के संकलन या मूल्यांकन के दौरान यदि किसी उत्तर पुस्तिका में मुद्रा मिलती है तो उसे नियमानुसार तत्काल राजकोष में जमा कराया जाएगा। साथ ही ऐसी घटनाओं की सूचना अविलंब जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी।

सेवानिवृत्त फौजियों के लिए किताब लिखने पर नए नियम? नरवणे विवाद पर सरकार ने अपना रुख किया साफ

नई दिल्ली। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों को लेकर चल रहे विवाद के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों के लिए पुस्तक लेखन संबंधी नए दिशानिर्देश लाने के किसी प्रस्ताव की उन्हें जानकारी नहीं है। एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए पहले से ही नियम और कानून मौजूद हैं, जिनमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य मुद्दा दिशानिर्देशों का अभाव नहीं है, बल्कि यह है कि क्या किसी मौजूदा नियम का उल्लंघन किया गया है। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, मुझे इस विशेष मुद्दे की जानकारी नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या नए दिशानिर्देशों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा दिशानिर्देश हैं और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू होता है। इस मामले में मुद्दा यह नहीं है कि दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैंय मुद्दा यह है कि क्या किसी ने उनका उल्लंघन करने की कोशिश की है। सार्वजनिक सूत्रों से मुझे पता चला है कि एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि, मुझे किसी नए दिशानिर्देश की जानकारी नहीं है, और वैसे भी, संवेदनशील मामलों में मौजूदा

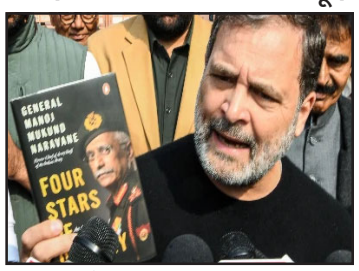

दिशानिर्देश और मौजूदा कानून, विशेष रूप से ओएसए, लागू होते हैं। यह घटना तब सामने आई जब राहुल गांधी ने लोकसभा में जनरल नरवणे की आत्मकथा श्फोर स्टार्स अ फ डेस्टिनीश का हवाला देने की कोशिश की, जिससे बजट सत्र के दौरान चीन के साथ २०२० के गतिरोध का मुद्दा चर्चा में आ गया और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस ने ६ फरवरी को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ र्म और समाचार मंचों पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया था कि श्फोर स्टार्स अ फ डेस्टिनीश पुस्तक की एक प्री–प्रिंट प्रति प्रसारित की जा रही है। स्पेशल सेल ने ष्अभी तक स्वींत न हुई पुस्तक के कथित रिसावध्उल्लंघनष् के संबंध में मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक के कथित रिसाव के संबंध में पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से लगातार दो दिनों तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, दोनों दिन पूछताछ कई घंटों तक चली, जिसमें जांचकर्ताओं ने पांडुलिपि और उसकी डिजिटल फाइलों के प्रबंधन और वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांच आगे बढ़ने के साथ प्रकाशन गृह के प्रतिनिधियों को आने वाले दिनों में फिर से बुलाया जा सकता है।

भाजपा फार्म ७ की आड़ में कटवा रही वोटः अखिलेश यादव

कानपुर। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे, बोले कानपुर को भाजपा ने बदनामपुर बना दिया। पाकिस्तान की चिंता करते करते पूरा बाजार चाइना को थमा दिया। अमेरिका से डील ने ढील हुई है क्योंकि गाय भैंस का चारा, मुर्गी का दाना भी अमेरिका से आएगा, ऐसे में हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष फजल महमूद के बहू बेटे को आर्शीवाद देने आए अखिलेश यादव उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर को ये भाजपाई लूट लेंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर में पुलिस–वकील की गुटबाजी, सीएमओ–डीएम की गुटबाजी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट भी कानपुर में ही लिखने की मामला सामने आया, काले नाले में भ्रष्टाचार समेत कई ऐसे मामले हैं जिसने कानपुर को बदनाम करके रख दिया। उन्होंने कहा कि जगह जगह जाम से ऐसे लगता है कि जैसे प्रशासन को मोतियाबिंद हो गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि गंगापुल पर घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं क्योंकि शहर की डिजाइन तक सही नहीं है, सड़कों के चौड़ीकरण का ठेका हो सकता है भाजपा वालों ने अपने लोगों को दे रखा हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ४ लाख करोड़ रुपये से जहाज खरीदने का ठेका दे

दिया है और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जब बाहर से सब कुछ खरीद रहे हैं तो मेक इन इंडिया कहां रह गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो रिवर फ्रंट की तर्ज पर कानपुर–कन्नौज और इटावा को मिलाकर कानपुर को एक बार फिर मेनचेस्टर बनाना चाहते थे। ट्रांसगंगा सिटी को बर्बाद कर दिया। वर्ष २०२७ में उत्तर प्रदेश की अवाम बदलाव चाहती है और बदलाव होते ही मैनचेस्टर का ख्वाब पूरा करेंगे। उन्होंने वादा किया कि लाल इमली को एक बार फिर चालू करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा पीडीए विशेषकर अल्पसंख्यकों का वोट कटवा रही है, फार्म ७ भरवाने की क्या जरुरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसी बड़ी कंपनी को हायर किया है जिसके माध्यम से वोट काटने का काम हो रहा है। इसका पता चलना चाहिए कि आखिर ये कौन सी कंपनी है। बीएलओ बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन सारा खेल ऊपर से है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया, सादी वर्दी में पुलिस वालों को लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन्होंने कहा कि वाराणसी में मूर्तियां तोड़ दीं, नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वह भी चोरी हो गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एआई ने तोड़ दीं। मुख्यमंत्री को एआई के बारे में पता ही नही है। दावा तो ये है कि लखनऊ से कानपुर ४५ मिनट में पहुंचा देंगे, 'उल्टी गणितवालों से सब पूछ रहे हैं कि दो स्मार्ट सिटी के बीच में ये जो गंगा ब्रिज पर ६० मिनट का जाम लगता है, वो इसमें शामिल है या अनुपूरक बजट की तरह इसकी बात अलग से की जाएगी। भाजपाइयों की यही सबसे बुरी बात है कि जिनता बताते नहीं हैं, उससे दोगुना छिपाते हैं।

जेलर आरके तिवारी हत्याकांड से चर्चा में आए शोएब किदवई की हत्या, नेशनल हाईवे जाम कर वकीलों ने मांगा न्याय

बाराबंकी। २७ साल पहले लखनऊ में राजभवन से कुछ दूरी पर जेलर आरके तिवारी हत्याकांड के बाद से बाराबंकी के शोएब किदवई उर्फ बाबी का नाम चर्चा में आया। यहीं से उनका नाम मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ गया। वह बंकी ब्लाक में ज्येष्ठ प्रमुख भी रहे, वकालत पेशा अपनाया और रहन सहन भी आम कर लिया पर मुख्तार का खास होने की पहचान वह मिटाने में नाकाम रहे। हालांकि ढाई दशक के बाद बाबी की हत्या के निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। बताते चलें कि जेल में सुधार के लिए चर्चित रमाकांत तिवारी की चार फरवरी १९९९ को हत्या कर दी गई थी। लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी सदाकांत के आवास से बैठक कर वह शाम सात बजे लौट रहे थे। राजभवन के पास पहुंचते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें छलनी कर दिया था। बाद में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, चर्चित छात्र नेता अभय सिंह समेत दर्जन भर से अधिक लोग नामजद हुए थे। नामजद लोगों में बतौर शूटर बाराबंकी के शोएब किदवई व देवरिया के रामू का भी नाम शामिल था। इस हत्याकांड की जांच के बाद मुख्तार बरी हो गए थे पर शोएब के साथ शार्प शूटर की पहचान ऐसी जुड़ी कि इसे मिटाना मुश्किल हो गया। जिला मुख्यालय पर डीएम आवास से कुछ दूरी पर रह रहे शुएब ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की और बसपा से जुड़कर राजनीति में दांव आजमाया, इसके बाद वह बंकी ब्लाक में ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख बने। आम रहन सहन की ओर बढ़े शोएब ने बाद में वकालत पेशा अपना लिया और तबसे कचहरी में ही समय देने लगे। इतना सब करने के बावजूद वह मुख्तार गैंग से जुड़ी पहचान मिटा नहीं सके। लोगों में उनकी हत्या की वजह को लेकर खासी चर्चा है। बता दें कि शोएब के बड़े भाई जावेद कचहरी में वकील हैं जबकि छोटा भाई इंग्लैंड में है। पत्नी शाजिया से १५ वर्षीय पुत्र अरमान पढ़ाई कर रहा है। इनकी ससुराल लखनऊ के मलिहाबाद में है। अधिवक्ता शोएब किदवई की हत्या को लेकर वकील समुदाय आक्रोशित हो गया है। दिनदहाड़े हत्या से गुस्साए वकील बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे बाद में कुछ ही दूरी पर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया। वकीलों ने ४८ घंटे के भीतर घटना के खुलासे का अल्टीमेटम दिया है। जिला मुख्यालय ही नहीं तहसीलों में वकील प्रदर्शनरत रहे। रामपुर जिले के बाद बाराबंकी में वकील शोएब किदवई की हत्या से अधिवक्ता समाज में खासा गुस्सा फैल गया है। एक के बाद एक घटनाओं को लेकर नाराज वकील पहले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां पर विरोध जताया गया। शाम होने तक यह भीड़ बढ़ गई और आक्रोश सड़क पर उतर आया। हंगामा करते हुए वकील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा की अगुवाई में नेशनल हाइवे पर बस अड्डे तक पहुंचे और यहां पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। वकील मृत अधिवक्ता का नाम मुख्तार गैंग से जोड़े जाने को लेकर खासे नाराज थे। इसके बाद एसपी से मिलकर दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि इस हत्या की घटना का ४८ घंटे के अंदर खुलासा किया जाए। यहां पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रितेश मिश्र, महामंत्री रामराज यादव आदि मौजूद रहे। फतेहपुर प्रतिनिधि के अनुसार स्थानीय बार के पदाधिकारियों ने विरोध जताया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुरानी कचेहरी से विरोध प्रदर्शन करते हुए नवीन कचेहरी परिसर में राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन तहसीलदार वैशाली अहलावत को सौंपते हुए मांग की कि प्रदेश में हो रही अधिवक्ताओं की हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जावे और मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को एक एक करोड की आर्थिक सहायता करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दी जाये। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, इन्द्रेश कुमार शुक्ला, राजीव नयन तिवारी, हरनाम सिंह वर्मा, ओम प्रकाश यादव, गणेश शंकर मिश्रा, प्रदीप कुमार निगम, श्रवण कुमार वर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

बख्शा नहीं जाएगा कोई भी अपराधीः लैंब र्गिनी हादसे पर बोले डिप्टी सीएम, विपक्ष को दिखाया आईना

भदोही। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम करती है और कानपुर लैंब र्गिनी कार दुर्घटना मामले में अदालत के फैसले का पालन करेगी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही जमानत दे दी गई थी। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले को संभालने को लेकर सरकार की आलोचना की है जिसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाठक ने कहा कि यादव को ष्तथ्यों के बारे में पता होना चाहिएष और अपने शासन के दौरान सक्रिय संगठित माफियाओं की संख्या पर गौर करना चाहिए। यहां सुरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद पाठक ने पत्रकारों से कहा, ष्हमारी सरकार अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम करती है। कोई

भी अपराधी, बड़ा या छोटा, बख्शा नहीं जाएगा। आज राज्य में एक भी संगठित गिरोह नहीं है।ष इस हफ्ते की शुरुआत में कानपुर में वीआईपी रोड पर शिवम मिश्रा नामक व्यक्ति ने अपनी तेज रफ्तार लग्जरी कार लैंब र्गिनी से छह लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। पाठक ने कहा कि मामला अदालत में है। मामले में आरोपी स्थानीय व्यापारी के बेटे मिश्रा को पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। मिश्रा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पेश किया गया, जिसने १४ दिन की न्यायिक हिरासत की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी और दोपहर बाद २०,००० रुपये के निजी मुचलके पर मिश्रा को जमानत दे दी। पुलिस ने दावा किया था कि मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर घूम रहा था। पाठक ने कहा, ष्मामला अदालत में है। हम चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे। अदालत जो भी फैसला लेगी, हम उसका सम्मान करेंगे।'

बंथरा इलाके में कार ने ऑटो और पैदल यात्रियों को टक्कर मारी, छह साल के बच्चे की मौत

लखनऊ। लखनऊ के बंथरा इलाके में हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात कार ने ऑटोरिक्शा और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। इस घटना में छह साल के बच्चे की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, बंथरा थाने को बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक अज्ञात कार ने एक ऑटो रिक्शा और सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारी। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात बताया कि घायलों की पहचान अरमान (१२), अवध बिहारी (४२), साधना वर्मा (३५), मीना देवी (६०) और दीक्षांत पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दीक्षांत की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पीड़ितों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जरूरी कार्रवाई की जा रही है और दुर्घटना में शामिल गाड़ी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

यूपी की १६ जिला कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकीः लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी समेत कई कोर्ट में मचा हड़कंप

लखनऊ। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी समेत प्रदेश के १६ जिला कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी शुक्रवार सुबह दी गई। यह धमकी सभी जिला जज के आधिकारिक ई–मेल के जरिये भेजा गया। जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पूरा कचहरी परिसर खाली कराया गया। पुलिस व बम निरोधक दस्ते ने सर्च अभियान चलाया। वहीं साइबर क्राइम की टीम ई–मेल भेजने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही है। लखनऊ में जिला कचहरी में चार घंटे तक सर्च अभियान चला, हालांकि कुछ भी हाथ नहीं लगा। परिसर की सुरक्षा के बंदोबस्त किये गये। जिला जज के आधिकारिक मेल आईडी पर शुक्रवार की दोपहर एक धमकी भरा ई–मेल आया जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आनन–फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वायड टीम ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आम लोगों का परिसर में प्रवेश रोक दिया गया। इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी के मुताबिक इस मेल के बारे में जिला जज की तरफ से सूचना दी गई थी। आधा दर्जन से अधिक टीमों ने पूरे कचहरी परिसर की तलाशी ली। अंदर मौजूद कई संदिग्ध दिखने वाले लोगों से पूछताछ की गई। सड़क किनारे, अधिवक्ताओं के चौम्बर, पार्किंग में खड़े दो और चार पहिया वाहनों की भी बम निरोधक दस्ते ने जांच की। कचहरी उड़ाने की धमकी के मेल की जानकारी परिसर में वकीलों, पैरोकार व अन्य लोगों को हुई तो अफरा–तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल बाहर से अंदर आने वालों को रोक दिया। पूरा परिसर खाली कराया गया। चौंबर और कोर्ट रूम में मौजूद अधिवक्ता और अन्य लोग भी काम बंद कर बाहर आ गए। पुलिस ने लगभग चार घंटे तक परिसर में तलाशी अभियान चला। इस दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला। इंस्पेक्टर के मुताबिक एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेल भेजने वाले के बारे में आईपी एड्रेस की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर क्राइम टीम की मदद भी ली जाएगी। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे कचहरी परिसर की तलाशी ली गई है। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। साइबर क्राइम व सर्विलांस की टीमों को मेल भेजने वाले के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लगाया गया है। इस मामले में अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।

बी.पी.एस पब्लिक स्कूल में कक्षा १२ के विद्यार्थियों का विदाई समारोह

के० के० शुक्ला

लखीमपुर खीरी। शहर के मेला मैदान रोड पर स्थित बी. पी. एस. पब्लिक स्कूल में कक्षा ११ के विद्यार्थियों द्वारा बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए हर्षोल्लासपूर्ण किंतु भावुक विदाई समारोह का

आयोजन किया गया। यह समारोह उनके इस विद्यालय के शैक्षणिक सफर का समापन दर्शाता है, जिसमें समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्मृतियों, उपलब्धियों और विकास की कहानियों भरी हुई हैं। कार्यक्रम का प्रारम्भ विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती प्रमोदिनी शुक्ला, एवं प्रधानाचार्या श्रीमती नीलम अवस्थी जी एवं विद्यार्थीयों के स्वागत से हुआ तत्पश्चात स्कूल कैप्टन आकाश तथा वाइस कैप्टन अभिश्री मिश्रा ने केक काटा। इसके पश्चात कक्षा ११ के विद्यार्थीयों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य, नाटक समूह गान प्रस्तुत किये गए द्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कक्षा १२ के विद्यार्थीयों द्वारा प्रस्तुत रैम्प व क रहा। जिसमें अर्पित वर्मा को मिस्टर बी. पी. एस. एवं अभिश्री मिश्रा को मिस बी. पी. एस. चुना गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती नीलम अवस्थी ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को दिये अपने संदेश में कहा, हमारी शुभकामनाएँ सदैव आपके साथ हैं। जहाँ भी जाएँ, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें और एक सच्चे, संवेदनशील व जिम्मेदार नागरिक बनें। समारोह का समापन निरंतर संबंध बनाए रखने तथा उच्च शिक्षा व करियर हेतु शुभकामनाओं के साथ हुआ।

इण्टरमीडिएट छात्र/छात्राओं का विदाई समारोह संपन्न

गोला गोकर्णनाथ खीरी। गुरुवार को स्थानीय विद्यालय विद्या कुँवरि स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन इण्टर कालेज के सभागार में कक्षा ११ के विद्यार्थियों ने इण्टर के विद्यार्थियों को विदाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र का अनावरण, पुष्पार्चन एवं वंदना के साथ हुई। इसके पश्चात प्रांजली, पीहू, अंशिका जायसवाल, शीतल वर्मा, उत्कर्ष मिश्रा, अंश शुक्ला आदि छात्र/छात्राओ ने अपने भावों को व्यक्त कर छात्र/छात्राओं को नित्य नई ऊंचाइयों को छूने तथा अपनी उपलब्धि सांझा करने के लिये उत्साह वर्धन किया। विद्यालय की बालिका विभाग की प्राचार्या श्रीमती मधु त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में बताया कि छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विद्यार्थी, अध्यापकों के कार्यों का विषय, अध्यापकों के विचारों का लक्ष्य और अध्यापकों के प्रयासों का प्रतिबिम्ब होते हैं।

यह सत्य है कि, हमने आप सभी को शिक्षित किया है हालांकि, यह भी सत्य है कि, हमने भी आप सभी से बहुत कुछ सीखा है। बारह साल का यह लम्बा सफर था हालांकि, आप सभी की भविष्य में कुछ बेहतर करने की दृढ़ इच्छा के कारण यह समय बहुत जल्दी बीत गया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कौशल किशोर मिश्रा ने परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले की सावधानियों, समय पर पहुचने एवं परीक्षा देते समय की जानकारियों पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्राचार्य महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने छात्र/छात्राओं को परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित अध्ययन, नियमित रिवीजन, और लिखकर अभ्यास करने महत्व पर प्रकाश डाला तथा साथ ही यह भी बताया कि सार्थक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना भविष्य की सफलता की नींव है। कार्यक्रम के अंत में सूक्ष्म जलपान कर विद्यार्थी प्रसन्नता पूर्वक विदा हुए।

दिनदहाड़े हत्या से अधिवक्ताओं में आक्रोश, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग

लखीमपुर खीरीधनिघासन। निघासन सिविल बार एसोसिएशन ने रामपुर बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता फारूख अहमद खां की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राजीव निगम को सौंपा है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने प्रदेश में लगातार हो रही अधिवक्ताओं पर हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की है। बार एसोसिएशन ने मृतक अधिवक्ता के परिजनों को ५० लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने,

प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और न्यायालय परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। एसोसिएशन ने सरकार से जल्द कार्रवाई कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, मुंबई में होगी इंटिमेट शादी, कृतिका कामरा

मुम्बई। अभिनेत्री कृतिका कामरा और क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर की शादी की खबरें जोरों पर हैं। दोनों ने हाल ही में रिश्ते को सार्वजनिक किया था और अब यह कपल अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जानकारी के मुताबिक, कृतिका और गौरव मार्च महीने में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। एक करीबी सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि शादी के सभी कार्यक्रम सोच–समझकर प्लान किए गए हैं और इसमें परिवार के लोग ही मौजूद रहेंगे। कृतिका का पूरा परिवार इस खास मौके के लिए दिल्ली से मुंबई आएगा। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, शादी के पहले दो दिन बेहद निजी रखे जाएंगे। इन दिनों में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। वहीं, शादी के तीसरे दिन एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त और मेहमान शामिल होंगे। शादी के आयोजन मुंबई के

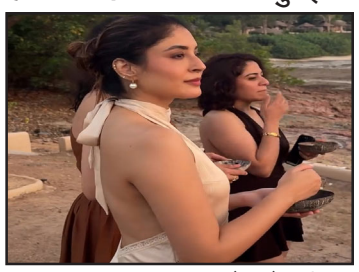

अलग–अलग इलाकों में किए जाएंगे। पहले दो दिन के कार्यक्रम बांद्रा और आसपास के इलाकों में होंगे, जबकि रिसेप्शन लोअर परेल में आयोजित किया जाएगा। कपल के एक करीबी ने पहले बताया था कि कृतिका और गौरव डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं चाहते। वे एक ऐसी शादी चाहते थे, जो उनकी सोच, उनकी पर्सनैलिटी और उनके रिश्ते को सही मायनों में दर्शाए। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में कृतिका ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक किया था। उन्होंने गौरव के साथ ब्रेकफास्ट डेट की कुछ कैंडिड तस्वीरें साझा की थीं। बात करें अगर कृतिका कामरा के करियर की तो, उन्होंने २००७ में टीवी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और 'कितनी मोहब्बत है' से घर–घर में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज, फिल्मों और वेब सीरीज में अलग–अलग तरह के किरदार निभाए। वहीं, गौरव कपूर एक जाना–पहचाना चेहरा हैं और क्रिकेट से जुड़े शो के लिए मशहूर हैं।

निजी सुरक्षाकर्मियों व सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की एसओपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निजी सुरक्षाकर्मियों एवं सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण को लेकर शुक्रवार को यूपी पुलिस ने स्टैंडर्ड अ परेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी है। जारी एसओपी के आधार पर प्रदेश में अब सुरक्षाकर्मियों को ट्रेनिंग

दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के मुताबिक, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–२००५ (पसारा एक्ट) बनाया गया था, जिसके आधार पर उप्र सरकार द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, २००६ बनायी गयी। उक्त नियमावली में वर्ष २०२३ में संशोधन करते हुए नई नियमावली वर्तमान में लागू की गई है। वर्ष–२००६ के शासनादेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, उप्र को पसारा का नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल ३०६७ लाइसेंस जारी किये जा चुके है। वर्तमान में गार्डो को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने एवं प्राइवेट सुरक्षा के गार्ड/सुपरवाइजरों की गुणवत्ता बढाने हेतु उप्र राज्य में प्रशिक्षण संस्थान को लाईसेंस प्रदान किये जायेगें। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, इससे अन्य प्रदेशों के अधिंत प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भरता समाप्त होगी, जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की आर्थिक लागत में कमी आने के साथ–साथ श्रम शक्ति की बचत होगी और उनके संचालन में सुविधा होगी। जबकि प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जिन क्षेत्रों में ये संस्थान स्थापित होंगे, वहां आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी एवं जनसामान्य में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी।

अभ्युदय योजना भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ाः गड़बड़ी मिलने पर संयुक्त निदेशक निलंबित

लखनऊ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोर्स कोअ र्डिनेटर पदों की चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार बिसेन को निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में वे निदेशालय से संबद्ध रहेंगे तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगे। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की एक गोपनीय शिकायत विभागीय मंत्री असीम अरुण को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जांच कराई गई। जांच के दौरान संयुक्त निदेशक की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इतना ही नही जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का मूल अभिलेखों से समुचित सत्यापन नहीं किया गया। साक्षात्कार और चयन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज विभागीय पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए। इतना ही नही चयन प्रक्रिया की निगरानी हेतु गठित समितियों द्वारा साक्षात्कार एवं सत्यापन कराए जाने का कोई प्रमाणिक रिक र्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर चयन की संस्तुति किए जाने से योजना की पारदर्शिता प्रभावित हुई। २९ अक्टूबर २०२५ को मिली शिकायत के बाद की गई जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार कोर्स कोअ र्डिनेटर पद के लिए यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन कई अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। ६९ अभ्यर्थियों की जांच में केवल २१ ही पात्र पाए गए थे।

प्यार और बदले की आग में तपती 'ओ रोमियो', शाहिद कपूर का दमदार अभिनय

मुम्बई। फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान खींच रही है। प्यार और बदले की भावना से बुनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म की कहानी में प्यार, दर्द, गुस्सा, जज्बात और इंसानी रिश्तों की कई परतें दिखाई गई हैं। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने कहानी और किरदारों को सोच–समझकर पेश किया है। फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी स्पेशल अपीयरेंस में हैं। फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जिन्होंने कहानी को संतुलित रखा है। छोटे–छोटे सीन, कैमरे की पकड़ और भावनाओं की गहराई यह दिखाती है कि हर सीन पर बारीकी से काम किया गया है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद दमदार हैं। शाहिद कपूर और अविनाश तिवारी के एक्शन सीन दर्शकों को बांधे रखते हैं। वहीं तृप्ति डिमरी भी एक्शन में चौंकाती हैं। फिल्म दर्शकों

की उम्मीदों पर खरी उतरती है। फिल्म का हर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह फिट बैठता है। शाहिद कपूर का किरदार उस्तारा उनके करियर के बेहतरीन रोल्स में से एक माना जा रहा है। उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली है। तृप्ति डिमरी का रोल अफशां अपनी मासूमियत और बदले की आग, दोनों को बखूबी दिखाती हैं। अविनाश तिवारी ने जलाल के रूप में दर्शकों को चौंका दिया है। उनका लुक, सिर पर बना टैटू और सख्त अंदाज किरदार को डरावना बनाता है। उनका अभिनय इतना अलग है कि कई जगह पहचानना मुश्किल हो जाता है। शाहिद और तृप्ति की जोड़ी नई होते हुए भी स्वाभाविक लगती है। वहीं नाना पाटेकर और फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकार फिल्म में जान डाल दिखते हैं। नाना पाटेकर के डायल ग्स सीधे दर्शकों पर गहरा असर छोड़ते हैं, वहीं फरीदा जलाल की दमदार लाइन्स फिल्म को मजबूती देती हैं। फिल्म में हास्य सीन्स भी रखे गए हैं, लेकिन उन्हें बेहद समझदारी से जोड़ा गया है। हास्य कहानी की गंभीरता को तोड़ता नहीं, बल्कि कुछ पलों के लिए राहत देता है। संगीत फिल्म की एक और बड़ी खासियत है। विशाल भारद्वाज का संगीत भावनाओं को और गहरा करता है। गाने कहानी के साथ चलते हैं। 'आशिकों की क लोनी' और 'पान की दुकान' जैसे गाने फिल्म में एनर्जी लाते हैं। डांस नंबर में दिशा पाटनी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री खास तौर पर ध्यान खींचती है। दोनों का डांस दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म के साथ अपनी शानदार फिल्मों की लिस्ट में एक और मजबूत नाम जोड़ दिया है। इससे पहले वे 'छिछोरे', '८३', 'तमाशा', और 'चंदू चौंपियन' जैसी यादगार फिल्में दे चुके हैं। 'ओ रोमियो' उनकी उसी सोच और सिनेमाई दृष्टि को आगे बढ़ाती है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक